आज ही के दिन 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था।

कम्प्यूटर लैब एवं पुस्तकालयों की स्थापना में लाएं तेजी

- पीएमश्री स्कूलों की समीक्षा के दौरान दिए मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने दिए निर्देश

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। पीएमश्री स्कूलों में कम्प्यूटर लैब एवं पुस्तकालयों के स्थापना में तेजी लायी जाए। कम्प्यूटर लैब अगले एक माह में की जाए स्थापित। यह निर्देश मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में पीएमश्री स्कूलों की समीक्षा के दौरान दिए।

उन्होंने कहा कि स्कूलों में पुस्तकालयों के लिए शीघ्र बजट आबंटित किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि 32 पीएमश्री स्कूलों में एकीकृत विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना में भी तेजी लायी जाए। जिनका बजट जारी किया जाना है, एक माह के भीतर बजट जारी कराया जाए। उन्होंने टिंकरिंग लैब शीघ्र उपलब्ध कराए जाने के लिए आईआईटी कानपुर से लगातार संवाद कर निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य को पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी पीएमश्री स्कूलों में खेल के मैदान उपलब्ध कराए जाने पर भी शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कुल 226 विद्यालयों को पीएमश्री विद्यालयों के रूप में चुना गया है। इसमें 34 प्राथमिक एवं 192 माध्यमिक विद्यालया शामिल हैं। इसके साथ ही 15 और अन्य विद्यालयों को स्वीकृति मिली है। बताया गया कि पीएमश्री के 22 कम्पोनेंट्स में से 16 को 100 प्रतिशत लागू कर लिया गया है। बाकि 6 कम्पोनेंट्स का कार्य विभिन्न चरणों में गतिमान है।

पीएमश्री स्कूलों की समीक्षा बैठक लेते मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन।

बुजुर्ग महिला के मकान पर ताला जड़कर फरार, सिटी मजिस्ट्रेट करेंगे जांच

- जिलाधिकारी ने 102 लोगों की सुनी समस्या, कई मामले मौके पर निपटाए

भास्कर समाचार सेवा

जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनते जिलाधिकारी सविन बसंल।

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बसंल ने सोमवार को ऋषिपर्णा सभागार में जनता दर्शन कार्यक्रम में जन समस्याएं सुनी। दूर दराज से पंहुचे लोगों ने 102 समस्याएं रखी। जिलाधिकारी ने मौके पर ही कई मामलों का ऑन द स्पॉट निस्तारण किया साथ ही कुछ प्रकरणों को इससे जुड़े विभागों को अग्रसारित करते हुए विधि सम्मत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उच्च प्राथमिकता पर उनका समाधान करना सुनिश्चित करें। जनता दरबार में प्रगति आजीविका स्वयं सहायता समूह की चार महिलाओं की आईडी का इस्तेमाल कर बिना उनकी जानकारी के दूसरे समूह की महिला द्वारा 5 लाख का ऋण लिए जाने की शिकायत पर डीएम ने फाइनेंशियल फ्रॉड के तहत केस दर्ज कराने के निर्देश दिए। सेलाकुई निवासी सरिता देवी ने भूमाफियाओं द्वारा उनके नाम रजिस्ट्री वाली भूमि पर जबरन कब्जा करने, रास्ता और सिंचाई नहर बंद कर उन्हें परेशान करने की शिकायत पर एसडीएम विकासनगर को जांच कर आख्या देने को कहा।

राजावाला निवासी पूर्व सैनिक की विधवा पत्नी पूर्णकला खत्री ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज न होने की शिकायत पर डीपीआरओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं आयुष वर्मा की उत्तरजीवी प्रमाण पत्र की मांग पर एसडीमए को प्राथमिकता पर मामले का निस्तारण करने को कहा। सहसपुर निवासी सुनीता ने अपने बेटे का जन्म प्रमाण पत्र न बनाने की शिकायत पर डीपीआरओ को समस्या का समाधान करने को कहा गया। डालनवाला में गली के सीवर लाइन को मुख्य सीवर लाइन से जोड़ने के लिए सड़क कटिंग की अनुमति चाहने पर एसई लोनिवि को प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा। साकेत कॉलोनी लेन नं-3 अजबपुर कलां में 200 मीटर सड़क बिटुमन निर्माण न किए जाने शिकायत पर लोनिवि को कारण सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने को कहा गया। रीठा मंडी में नगर निगम की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर एमएनए को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सहस्रधारा रोड़ पर ग्राम समाज की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य करने की शिकायत पर एसडीएम और एमडीडीए को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस दौरान पीडित लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। जनता दरबार में अपर जिलाधिकारी (एफआर) केके मिश्रा, एसडीमए स्मृता परमार, एसडीमए अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, तहसीलदार सुरेन्द्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

उत्तराखंड के युवाओं को बंधक बनाकर कराई साइबर ठगी

मोबाईल लोकेशन व डिजीटल साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रदीप कुमार को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। रैस्क्यू अभियान के तहत थाईलैंड, म्यांमार, बैंकाक में नौकरी के लिए विदेश गए विभिन्न युवाओं को भारत वापस लाया गया जिनको एजेंटों के माध्यम से अच्छी नौकरी व सैलरी बताकर भारत से बाहर भेजा गया था परन्तु भारतीय नागरिकों को वहां पर बंधक बनाकर उनसे साईबर ठगी कराई जा रही थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि प्रकरण में विदेश से वापस भारत लाए गए जनपद उधम सिंह नगर के कुल 7 नागरिकों से गहन पूछताछ के पश्चात जानकारी मिली कि जनपद में कुछ एजेंटों द्वारा विदेशी एजेंटों से संपर्क कर युवाओं को अच्छी नौकरी व सैलरी का लालच देकर मोटी धनराशि लेकर विदेश भेजने का कार्य किया जा रहा था, जिनसे वहां पर जबरन साईबर ठगी का अपराध कराया जा रहा था जिसमें बाद जांच सुनील कुमार, अशोक, पिंकी, नीरव चौधरी, प्रदीप निवासी काशीपुर/जसपुर जनपद उधम सिंह नगर एवं धन्जय निवासी महाराष्ट्र के नाम प्रकाश में आए जिसमें उच्चाधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज कर गहनता से विवेचना करने के आदेश दिये गए थे। विवेचना के दौरान साईबर क्राईम पुलिस द्वारा एजेंटों के विभिन्न बैंक खातों, मोबाइल नंबरों/व्हाट्सअप आदि की जानकारी के लिए डेटा प्राप्त किया गया। विवेचना के दौरान नामजद आरोपी की मोबाईल की लोकेशन व अन्य डिजीटल साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रदीप कुमार के आवास पर पहुंचे जहां पर प्रदीप कुमार निवासी काशीपुर ऊधम सिंह नगर मौजूद मिला।

एसटीएफ की गिरफ्त में युवाओं से ठगी करवाने का आरोपी।

आरोपी को हिरासत में लेकर विस्तृत पूछताछ किये जाने पर प्रकाश में आया प्रदीप कुमार द्वारा मनीष चौहान निवासी दडियाल काशीपुर से चालीस हजार रूपये का कमीशन प्राप्त कर पीडित अयाज को बैंकांक थाईलैंड में डिजिटल मार्केट की नौकरी के लिये भेजा गया था। माह अगस्त में अयाज बैंकाक (थाईलैंड) पहुंच गया। इसके बाद अयाज सीधे मनीष चौहान के ही संपर्क में रहा। मनीष ने अयाज को बैंकाक (थाईलैंड) से केके पार्क म्यांमार (बर्मा) तक अवैध रास्तों से पहुंचाया जिसके बाद आरोपी का पीड़ित से संपर्क नहीं रहा। इससे पहले भी मनीष ने आरोपी को 2 बार माह जुलाई में दस हजार रुपये तथा माह अगस्त में पांच हजार रूपये आनलाईन स्थानांतरित किये थे। मनीष ने अयाज के बदले आरोपी को पैतालीस हजार रुपये का कमीशन दिया था।

डाटा एंट्री का कार्य बताकर कराई जाती थी युवाओं से साइबर ठगी

पीडितों को विदेश में अच्छी सैलरी पर नौकरी लगाए जाने का लालच देकर व संबंधित देशों के एजेंटों से मिलीभगत कर व्हाटसप के माध्यम से पीडितों की डिटेल उपलब्ध विदेशी एजेंटों को उपलब्ध करायी जाती थी एवं पीड़ितों को कम्प्यूटर डाटा एंट्री का कार्य बताया जाता था जिसके एवज में मोटी धनराशि पीडित व पीड़ित परिवार से ली जाती थी परन्तु विदेश पहुंचने के पश्चात वहां पर पूर्व से ही आवेदकों को रिसीव करने के लिए एजेंट मौजूद रहते थे। जिसकी जानकारी भारतीय एजेंटों को रहती थी विदेशी एजेंट द्वारा पीड़ितों को अपने साथ अज्ञात नदी नालों व जंगल के रास्तों से अंजान स्थान ले जाया जाता था जहां पर चाईनीज एजेंट व टीम लीडरों द्वारा पीड़ितों से जबरन साईबर धोखाधडी कराई जाती थी जिसमें विदेशी एजेंटों द्वारा विभिन्न देशों की डेली वर्किंग ऑनलाईन साईट्स को हैक कर पीड़ितों को दिया जाता था।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन वित्तीय एवं भौतिक प्लान तैयार करने के दिए निर्देश

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में जाइका से वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत उद्यान विकास परियोजना की उच्च स्तरीय/संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को परियोजना का वित्तीय एवं भौतिक प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों में भ्रमण कर समीक्षा कर फीडबैक लेने के लिए लगातार दौरे करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य विभागों की फल एवं सब्जियों से जुड़े आजीविका की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्ययोजना जनवरी माह तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए।

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

पत्रांकः3785/निविदा-निर्माण/2025-26 दिनांकः24 नवम्बर, 2025

निविदा सूचना

नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण / मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु नगर निगम ऋषिकेश के पंजीकृत ठेकेदारों से शील बन्द निविदाएँ दिनाँक 09.12.2025 को दोपहर 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं उपस्थित निविदादाताओ के रागक्ष तद्दिनॉक को अपराहन 3:30 बजे निविदा समिति, नगर निगम, त्रऋषिकेश द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र दिनाँक 01.12.2025 से 08.12. 2025 को दोपहर 2:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम ऋषिकेश में किसी भी कार्यालय दिवस में क्रय किये जायेंगे। निविदा की शर्ते एवं विस्तृत विवरण/जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश से प्राप्त की जा सकती है।

(दिनेश प्रसाद उनियाल)
अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम ऋषिकेश।

शांत फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले एसआईआर विरोधी: भट्ट

- प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने वाली मंशा रखने वालों के ताबूत पर आखिरी कील: भाजपा

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। भाजपा ने एसआईआर की प्रक्रिया को प्रदेश में डेमोग्राफी बदलने की मंशा के ताबूत पर आखिरी कील साबित होने वाला बताया है।

प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सवाल कसते हुए कहा कि विपक्ष को क्यों लगता है जो भी फर्जी नाम मतदाता सूची से हटे हैं या हटेंगे हैं वो सभी उनके ही समर्थक होंगे? यह कहीं न कहीं कांग्रेस और विपक्ष के मन में खोट का संकेत करती है। भट्ट ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर को लेकर विपक्षी आपत्तियों को दरकिनार करने को भट्ट ने इसे संवैधानिक प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि आजादी के बाद 2004 तक देश में 8 बार यह प्रक्रिया पूरी की गयी है। लेकिन तब किसी तरह की आपत्ति राजनैतिक दलों द्वारा नहीं की गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुष्टिकरण की राजनीति के चलते इस वैधानिक प्रक्रिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। जबकि चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है कि इस पुनरीक्षण के तहत जो मतदाता मृत हो गए, दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो गए हैं या मतदाता मानकों को पूरा नही करते हैं, केवल उनका नाम ही हटाया जाएगा।

गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं कार्य: गणेश जोशी

- एमडीडीए के माध्यम से मसूरी क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की

भास्कर समाचार सेवा

एमडीडीए अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा करते मंत्री गणेश जोशी।

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सोमवार को हाथीबड़कला स्थित अपने शासकीय आवास में एमडीडीए अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा किया जाए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिन विकास कार्यों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, उनके लोकार्पण की तैयारी तुरंत शुरू की जाए तथा जिन कार्यों का शिलान्यास प्रस्तावित है, उनसे संबंधित सभी कागजी कार्यवाही समय पर पूर्ण की जाए।

उन्होंने बुरासखंडा एवं सुवाखोली, सालावाला, दून विहार, गल्जवाड़ी, गंगोल पंडितवाड़ी, भद्रराज मंदिर, सिल्ला, मीठीबेड़ी तथा मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत प्रस्तावित सड़क निर्माण, आंतरिक सीसी सड़कें, सुरक्षात्मक कार्य, स्ट्रीट लाइटें, सोलर लाइटें, पार्क निर्माण सहित सौंदर्यकरण एवं सुधारीकरण कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने वन स्वीकृति, रिटेंडरिंग तथा शासन स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने को कहा।

काबीना मंत्री ने देहरादून के कनक चौक स्थित जनरल बिपिन रावत पार्क में सौंदर्यकरण कार्यों को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया जा सके। इसके साथ ही, मंत्री जोशी ने देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के तहत राजपुर के काठबंगला क्षेत्र के बेघर हो रहे लोगों के पुनर्वास एवं जनहित के दृष्टिगत व्यावहारिक समाधान सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बैठक में सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, ईई सुनील कुमार, ईई अतुल गुप्ता, पूर्व पार्षद मंजीत रावत सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

यूजेवीएन लिमिटेड
मुख्यालय "उज्ज्वल" महारानी बाग, जी0एम0एस0 रोड, देहरादून–248006
दूरभाषः 0135–2763808, फैक्स– 0135–2763508
सी0आई0एन0 सं0: U40101UR2001SGCO25866 | वेबसाइटः www.ujvnl.com

पत्रांक–924 **निविदा सूचना** दिनांक– 24/11/2025

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (अनु0), खोदरी विधुतगृह, इच्छुक निविदादाताओं से मुहरबंद निविदायें आमन्त्रित करता है। निविदाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः
नि0सं0:18/EE(Maint.)/Khodri/2025-26
कार्य का नामः खोदरी विधुतगृह की मशीन 02 की टरबाईन एवं सहायक प्रणालिया के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।
अनुमानित लागत (लाख में): रू. 09.75 (जीएसटी अतिरिक्त),
वेबसाईट पर निविदा प्रपत्र की उपलब्धता की तिथि : 26.11.2025,10.00 बजे
निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि:16.12.2025,16.00 बजे
अन्य जानकारी हेतु कृपया हमारी वेबसाईट देखें। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाईट **www.ujvnl.com** से डाउनलोड किया जा सकता है।

अधिशासी अभियन्ता (अनु0) खोदरी विधुत गृह
"बिजली के दुरूपयोग से बचें"

फार्म जी
रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण
गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियमन 36ए (1) के तहत)

प्रासंगिक विवरण		
1.	कॉर्पोरेट देनदार का नाम PAN/CIN/LLP नंबर के साथ	**गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** U31300WB1961PLC025104
2.	पंजीकृत कार्यालय का पताः	वर्तमान पंजीकृत कार्यालयः En-62, सेक्टर-V 7वीं मंजिल, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत, 700091.
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://guptapower.com/
4.	उस स्थान का विवरण जहां अधिकांश अचल संपत्तियां स्थित हैं	कंपनी के पास भारत भर में कई ईपीसी साइटों के साथ-साथ खुर्दा-ओडिशा (पूर्वी भारत), गुम्मुदीपोंडी - चेन्नई (दक्षिण भारत) और काशीपुर-उत्तराखंड (उत्तर भारत) में स्थित सुविधाओं के साथ भौगोलिक रूप से विविध विनिर्माण आधार है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसकी अन्य अचल संपत्तियाँ राजारहाट (पश्चिम बंगाल) में स्थित हैं, साथ ही ओडिशा के जिलों और हलोल (गुजरात) में विभिन्न भूमि पार्सल भी हैं।
5.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो में एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम-मिश्र धातु, और एल्यूमीनियम-स्टील प्रबलित कंडक्टर, उच्च-तनाव और कम-तनाव बिजली केबल, नियंत्रण केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिग्नल केबल, एरियल बंच्ड केबल और औद्योगिक केबल शामिल हैं। कंपनी 'राइनो' ब्रांड नाम के तहत बिजली परिवर्तन स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइनों आदि और घरेलू केबल खुदरा क्षेत्र के लिए ईपीसी अनुबंध भी लेती है। कुल क्षमता लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी।
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/ सेवाओं की मात्रा और मूल्य	ज्ञात नहीं* *नोटः अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में उत्पादों की बिक्री 34,59,77,70,000/- रुपये थी और वित्त वर्ष 2021-22 में सेवाओं की बिक्री 2,44,73,44,000/- रुपये थी।
7.	कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या	ज्ञात नहीं* *नोटः काशीपुर (उत्तराखंड) सुविधा में परिचालन जारी है। सीडी की परिचालन आवश्यकताओं के आधार पर, वर्तमान में तैनात कार्यबल - कर्मचारियों और संविदा कर्मियों सहित - लगभग 500 कर्मियों तक है।
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (शेड्यूल के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं के लिए प्रासंगिक तिथियों सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं :	विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल द्वारा यहां मांगा जा सकता है : ip.guptapower@gmail.com
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां उपलब्ध है	समाधान आवेदकों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 29ए के तहत पात्र होना चाहिए। विवरण विस्तृत IEOI में उपलब्ध हैं, जिन्हें ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मांगा जा सकता हैः ip.guptapower@gmail.com
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	10 दिसंबर, 2025
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	20 दिसंबर, 2025
12.	अनंतिम सूची के आवेदकों पर आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26 दिसंबर, 2025
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	30 दिसंबर, 2025
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	03 जनवरी, 2026
15.	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	03 फरवरी, 2026
16.	EOI जमा करने के लिए प्रक्रिया ईमेल आईडी	ip.guptapower@gmail.com

दिनांकः 25 नवंबर 2025
स्थानः सूरत

एसडी/- **सीए. प्रदीप कुमार काबरा**
मेसर्स गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए आईआरपीओआरपी
आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P01104 /2017-18/11790
ईमेलः ip.guptapower@gmail.com

वेव्स फिल्म बाज़ार में देश-विदेश के फिल्म निर्माता और निर्देशकों ने उत्तराखंड में शूटिंग को रुचि दिखाई

विश्व प्रसिद्ध नंदादेवी राजजात यात्रा के बारे में दी गई जानकारी

भास्कर समाचार सेवा

देहरादून। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आयोजित वेव्स फिल्म बाज़ार में उत्तराखंड पवेलियन सभी फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है।

उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने बताया कि फिल्म बाज़ार में उत्तराखंड राज्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पवेलियन में देश विदेश के फिल्म निर्माता और निर्देशकों की ओर से राज्य की फिल्म नीति के बारे में जानकारी ली गई। बंगाली, तमिल, मलयालम, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के फिल्म निर्माताओं द्वारा भी फिल्मों की शूटिंग में रुचि दिखाई गई है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहयोग एवं सुविधाओं की सराहना की।

निर्माता व निर्देशकों के साथ चर्चा करते नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय।

कई विदेशी फिल्म निर्माता और निर्देशकों द्वारा उत्तराखंड में शूटिंग करने पर सहमति प्रदान की गई है। फिल्म बाजार में आगामी वर्ष 2026 में होने वाली राजजात यात्रा के बारे में भी फिल्म निर्माताओं को जानकारी दी गई, जिसमें कई विदेशी फिल्म मेकर द्वारा डॉक्यूमेंट्री शूट करने की बात की गई है।

डॉ उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए निर्देशों का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड की फिल्म नीति की सराहना देश दुनिया में हो रही है। उत्तराखंड पवेलियन में ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर सुवीं ग्राहम द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा आगामी फरवरी माह में उत्तराखंड भ्रमण कर शूटिंग लोकेशन देखने आएंगी।

इसके साथ ही कई देशों के प्रतिनिधियों द्वारा राज्य की फिल्म नीति के बारे में जानकारी ली गई। अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माता के सीईओ अरफ़ी लांबा ने द्वारा भी राज्य की फिल्म नीति की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि उनकी कम्पनी देश विदेश के फिल्म निर्माताओं के साथ कार्य करती है। उनका प्रयास रहेगा कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को उत्तराखंड लाया जाए। सूचना मंत्रालय, भारत सरकार डायरेक्टर फिल्म्स राजेश कुमार शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा भी उत्तराखंड पवेलियन का भ्रमण किया गया।

उत्तराखंड को पीएमजीएसवाई-1 के तहत 130 करोड़ रूपए किए जारी

देहरादून। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना -1 के अंतर्गत किये गए कार्यों के लंबित भुगतान के लिए 130.9680 करोड़ रुपये जारी किये हैं। स्वीकृत धनराशि को पीएमजीएसवाई-I के 31 मार्च 2025 तक बनी देनदारियों के भुगतान के लिए जारी किया गया है। ये स्वीकृति सिर्फ़ 31 दिसंबर तक वैध रहेगी और इस तिथि के बाद इसमें से कोई भी खर्च नहीं किया जाएगा। इस स्वीकृत धनराशि से केवल उन कार्यों का भुगतान होगा जो 31 मार्च तक पूरे हो गए हों या फिर उन कार्यों का कुछ भाग जो उक्त तिथि तक पूरा हो गया हो। राज्य को बाकी हिस्सा सिर्फ़ स्टेट फंड से पूरा करना होगा। योजनाओं का भुगतान होना है, जिनमें से 212 सड़कें और 172 पुल शामिल हैं